प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी दिशा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (टी0जी0एस0) के निर्बन्धनों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, जैसा कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा विचार किया गया था।

2. इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय–1 में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों के लेखों पर प्रेक्षण एवं टिप्पणियों सहित उनके किया कलापों का संक्षिप्त परिचय है तथा अध्याय–2 में (i) जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (ii) बारहवे वित्त आयोग अनुदान – शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों के उपभोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय–3 अनुपालन लेन–देनों की लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित है।

3. प्रतिवेदन में उद्धृत प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2007–08 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा/जांच के क्रम में प्रकाश में आये थे। अप्रैल 2007 से मार्च 2008 की अवधि में 7 नगर निगमों, 39 नगर पालिका परिषदों और 60 नगर पंचायतों के लेखे व अन्य अभिलेखों की जांच की गयी थी।